Privatisation of Power plants in Gujarat

4448. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of POWER be pleased to state:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for privatisation of power plants in Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) the stage at which this proposal stands; and

(d) the reasons for the privatisation of these power plants in that State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) Gujarat Electricity Board (GEB) proposes to transfer the 135 MW combined cycle gas based power plant at Utran to the newly formed Gujarat State Electricity Corporation Ltd. at a value of Rs. 312 crores which would form the equity of GEB in the new Company. Thereafter, GEB proposes to offload a percentage of its shareholding in the market. GEB would also go to the capital market through this Company.

(c) The valuation of the 135 MW Utran plant has been completed and the new Company has been formed.

(d) Privatisation of this power plant through corporate structure will enable GEB to raise funds for impelmenting other thermal power plants of a total capacity of 495 MW.

विद्युत परियोजनाओं में विदेशी निवेश

4449. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी निवेशकों के स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों को न्याय संगत ठहराने के लिए उनकी अधिष्ठापित क्षमता को अतिशयोक्तिपूर्ण बताया जा रहा है ;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्ड को वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने हेतु उनमें कोई उद्देश्यपूर्ण सुधार किया जा रहा है ।

(ग) क्या प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के अभाव में विदेशी भारतीय उपभोक्ताओं से पंजीकृत संसाधनों उपकरणों और ईधन आदि का बहुत अधिक किराया ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उर्मिलाबेन पटेल चिमनभाई पटेल) : जी नहीं ।

(ख) जी, हां । सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का नियमित और तत्काल भुगतान करना, ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना जिसके द्वारा राज्य बिजली बोर्ड (एस. ई. बी.) अपनी विद्युत उत्पाद लागत, खरीद, आपूर्ति और आय की निर्धारित दर के अनुरूप औसत टैरिफ प्राप्त कर सकें ; पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना, इत्यादि शामिल हैं ।

(ग) जी, नहीं । उर्जा के लिए टैरिफ का निर्णय भारत सरकार की दिनांक 30-3 1992 की अधिसूचना और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार किया जाता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Applicants or power projects

4450. SHRI T. VENKATRAM REDDY:

SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the names of the existing applicants for power projects in India;

(b) what is their background and financial strengths;